ISSN: 2456–4397 RNI No.UPBIL/2016/68067 Vol-6* Issue-2* May- 2021
Anthology : The Research

पशुधन विकास की राजस्थान राज्य मे वर्तमान आर्थिक समीक्षा

Current Economic Review of Livestock Development in Rajasthan State

Paper Submission: 02/05/2021, Date of Acceptance: 13/05/2021, Date of Publication: 24/05/2021

नीलू चतुर्वेदी
शोध छात्रा,
भूगोल विभाग,
महर्षि दयानन्द सरस्वती
विश्वविद्यालय,
अजमेर, राजस्थान, भारत

सारांश

भूगोल भूतल पर होने वाली भौतिक व मानवीय अन्तः क्रियाओं का अध्ययन है। मानव ने भूतल पर अपने कार्यों से भौतिक तत्वों में परिवर्तन करके आर्थिक व सांस्कृतिक भू–दृश्यों का विकास किया है। भारतीय अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि आधारित है। कृषि न केवल कृषक समुदाय के जीवन–यापन का साधन है अपितु विभिन्न उद्योगों के लिए कच्चा माल भी उपलब्ध करवाती है। देश की कुल जनसंख्या का दो तिहाई भाग वर्तमान समय में भी कृषि पर निर्भर है। देश में जलवायु विभिन्नता के कारण कृषि पद्धतियाँ एक समान न होकर विभिन्नताएँ धारण किए हुए है।

पूर्व–पाषाणकाल में वनवासी मानव जंगली भैंसा, गोपशु, शूकर, कुत्ता, हाथी, चीतल, नीलगाय, बंदर, गैंडा, हिरण, तेंदुआ, बाघ, पक्षी, मछली, कछुआ आदि से भली–भाँति परिचित था तथा उनका शिकार करके अपना पेट भरता था।

प्रागैतिहासिक काल में शिकार की अनिश्चितता तथा भोजन की समस्या सुलझाने के लिए मनुष्य के साथ ही कृषि एवं पशुपालन अपनाया।

उत्तर पाषाण काल में मानव के भोजन में माँस, दूध, अनाज, कंद, फल आदि भोजन के भाग थे। पशु बलि देने की प्रथा प्रचलित हो गई थी।

धातु काल में मनुष्य ने पशुओं से होने वाले लाभों को अच्छी तरह से समझा जिसके फलस्वरूप पशुपालन के विकास में तेजी आई।

भारतीय परिवेश में कृषि के साथ–साथ पशुपालन भी प्राचीन काल से सम्पूरक व्यवसाय के रूप में भूमिका निभा रहा है। पशुपालन न केवल दुग्ध उपलब्ध करवाता है। अपितु वर्तमान समय में भी कृषि से संबंधित छोटे–बड़े कार्य सम्पन्न करवाने एवं उपभोक्ता उद्योगों के लिए सामग्री प्रदान करने में तथा खाद्य सुरक्षा के आधार प्रदान करता है। पशुपालन का राष्ट्रीय आय में आज भी एक विशेष स्थान है। यह व्यवसाय ग्रामीण कृषक समाज को न केवल खाद्य उत्पाद (दूध, मांस, अण्डे) उपलब्ध करवाता है। अपितु रोजगार में भी स्थान बनाये हुये है।

भारत के विभिन्न हिस्सों में भौगोलिक कारकों के कारण कृषि के समान पशुपालन की विभिन्न पद्धतियों में भी भिन्नता पाई जाती है। पशु लाखों लोगों के लिए सस्ते पौष्टिक आहार उपलबध कराने के अलावा कृषकों के परिवार की आय का प्रमुख स्त्रोत है। विशेषतः भूमिहीन मजदूरों, छोटे और सीमांत किसानों और महिलाओं के लिए महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते है, क्योंकि भूमिहीन मजदूरों के पास वर्ष भर करने के लिए कार्य नहीं होते परन्तु पशुपालन सतत् व्यवसायिक प्रक्रिया है। इससे निरन्तर रोजगार प्राप्त कर भूमिहीन मजदूर आय का अच्छा साधन प्राप्त कर लेते है। छोटे और सीमांत किसानों का आय स्तर निम्न ही होता है। अतः वे अल्प भूमि में अत्यधिक लाभ को पशुपालन द्वारा प्राप्त कर सकते है तथा बनती, बिगड़ती कृषि परिस्थितियों में भी निरन्तर आर्थिक लाभ कमा सकते है।

Geography is the study of physical and human interactions on the surface. Humans have developed economic and cultural landscapes by changing physical elements through their actions on the ground floor. Indian economy is mainly agriculture based. Agriculture is not only a means of livelihood for the farming community but also provides raw material for various industries. Two-thirds of the total population of the country is still dependent on agriculture. Due to the climatic variation in the country, the agricultural practices are not uniform but have variations.

Due to the geographical factors in different parts of India, different methods of animal husbandry like agriculture are also found to differ. Animals are the main source of income for the family of farmers apart from providing cheap nutritious food to millions of people. Especially for landless labourers, small and marginal farmers and women, because landless laborers do not have work to do throughout the year, but animal husbandry is a continuous occupational process. Due to this, the landless laborers get a good source of income by getting continuous employment. The income level of small and marginal farmers is low. Therefore, they can get huge profit in small land by animal husbandry and can earn continuous economic profit even in the deteriorating and deteriorating agricultural conditions.

मुख्य शब्द : कृषि, पशुपालन, भारतीय अर्थव्यवस्था।
Agriculture, Animal Husbandry, Indian Economy.

प्रस्तावना

पशुपालन में व्यवहारिक रूप से देखा जाए तो सर्वाधिक श्रम महिलाओं का लगता है। पशुपालन से जुड़े सभी आधारीकृत कार्य महिलाओं के द्वारा ही सम्पनन किए जाते है तथा इस रोजगार से महिलाओं को सशक्त बनाया जा सकता है। उन्हें घरेलू कार्यों के साथ–साथ व्यापारिक दक्षता भी प्रदान की जा सकती है। जो सांस्कृतिक दृश्यों में उनकी प्रभावी भूमिका को सुनिश्चित करेगी। भारतीय जन–मानस ने पशुओं को अपनी संस्कृति में विशेष स्थान प्रदान किया है। विशेषतः दुधारू पशुओं की यहाँ पूजा भी की जाती है। बड़े उपलक्ष्य पर उनका विशेष महत्त्व होता है। जैसे दीपावली पर्व पर गोवंश का पूजन लक्ष्मी मानकर किया जाता है। साथ ही राजस्थान के पशु मेले सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को सुदृढ़ करने में अपना महत्त्वपूर्ण स्थान रखते हैं।

सामाजिक दृष्टिकोण से कृषक समुदाय ने पशुपालन को आवश्यक माना है। पशुधन कृषकों के भावनात्मक पहलू को भी प्रभावित करते है। राजस्थान राज्य के कई क्षेत्रों में विवाह समारोह में वधु पक्ष की ओर से पशुधन भेंट स्वरूप प्रदान किया जाता है। राजस्थान के कई अंचलों में आज भी पशुओं को परिवहन के रूप में प्रयोग लाया जाता है। कृषक समुदाय आर्थिक व सामाजिक स्वरूप की मौलिकता से कृषि कार्यों पर आश्रित है। अतः उनका सामना त्वरियोगदान है तथा देश के सकल घरेलू उत्पादन (Gross Domestic Production) में वर्तमान दरों पर पशुधन ने 3.9 प्रतिशत (2013–2014) का योगदान दिया है।

पशुपालन सीमांत कृषकों, कृषि मजदूरों तथा बेरोजगार युवकों के लिए अतिरिक्त आय तथा रोजगार का एक लोकप्रिय साधन है। पशुपालन से प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में लगभग दो करोड़ लोगों को रोजगार मिलता है जिसमें महिलाओं की भागीदारी लगभग 70 प्रतिशत है। ग्रामीण इलाकों में रोजगारोन्मुखी व्यवसाय में कृषि आधारित रोजगारों की अपेक्षा पशुपालन आधारित व्यवसाय को अधिक लोगों द्वारा रोजगार साधन के रूप में अपनाया जाता है। इसके अतिरिक्त पशुओं से प्राप्त रक्त, चर्ती, हड्डियाँ तथा खाल कई प्रकार के उद्योग–धंधों की प्रमुख कच्ची सामग्रीयाँ है। समग्र कृषि उत्पादों से प्राप्त आय में पशुपालन से प्राप्त लगभग एक चौथाई भाग में, भारवाही पशु शक्ति (Animal draft power) का मूल्य सम्मिलित नहीं है। एक आंकलन के अनुसार पशु शक्ति का योगदान 30,000 मेगावाट बिजली ऊर्जा या 40 मिलियन अश्व शक्ति 10,000 करोड़ रू. के बराबर आता है।

भारतीय पशुधन गणना (2012) के पूर्णावलोकन से यह सारांश सामने आता है कि देश के 32,87,263 वर्ग किमी. क्षेत्रफल में 1,210,854,977 मिलियन (जनगणना 2011) लोग (382 व्यक्ति प्रति वर्ग. किमी.) रहते है। इस जनसंख्या का 72.22 प्रतिशत भाग आज भी ग्रामीण तथा शेष शहरी भारत में निवास कर रहा है। देश के संपूर्ण क्षेत्रफल 6,75,538 वर्ग किमी. (20.55 प्रतिशत) वन क्षेत्र (Forest Cover) के अधीन है। पशुगणना रिपोर्ट की समीक्षा में पशुपालन एवं डेयरी विभाग, कृषि मंत्रालय, भारत सरकार का यह निष्कर्ष है कि पिछली पशुगणना (2007) की तुलना में देश में संकर गोपशुओं एवं भैंस की संख्या में क्रमशः 22.8 प्रतिशत एवं 8.9 प्रतिशत की वृद्धि हुई है जबकि देशी गोपशु कम हुए है जिससे यह स्पष्ट होता है कि 2007 की तुलना में देश की पशु संख्या में कमी आई है।

साहित्यावलोकन

एल रामचन्द्रन 1977 – ''भारत की खाद्य समस्या का एक नया दृष्टिकोण एलाइड पब्लिशर्स मुम्बई ने पशुचारण दुग्ध उत्पादन और पशु खाद्य पदाथ्रे का अध्ययन किया। यह अध्ययन हमें पशु प्रबन्धन की अवधारणा से तथा बढ़ते व्यावसायिक विकास से अवगत करवाता है।

1. एन के नायर 1979 – ''प्रगतिशील केरल में दुग्ध उत्पादन'' प्रस्तुत अध्ययन में विपरीत परिस्थितियों में पशु उत्पाद तथा कृत्रिम गर्भाधान से विकसित तन्त्र प्रणाली पर कार्य किया गया।

एसी गंगवार व आई जे सिंह 1979 – हरियाणा में पाये जाने वाली गायों के दुग्ध उत्पादन के मूल्य पर भौसामिक अन्तर के प्रभाव की समीक्षा की गयी।

ए.एच.सोमजी 1980 ने गुजरात राज्य के सेड़ा जिले में निम्न वर्गों के द्वारा दूध व्यवसाय में भागीदारी और सकारी संघों की कृषक समाज के प्रति मिलनसारिता का अवलोकन कर कार्य को अन्य स्थलों पर उन्नत बनाये जाने की दिशा दी।

जे.एस. चावला व एम.एस. गिल 1979 ने अमृतसर दुग्ध क्षेत्र को वहां के दुग्ध संयंत्र को स्थापित करने में होने का प्रभाव का अध्ययन कर कृषि सहयोगी व्यवसाय का पशुपालन को स्थान दिया।

ए. आर. पुरोहित 1979 – ग्रामीण आर्थिक विकास में संकर नस्ल का अध्ययन बढ़ती जनसंख्या आर्थिक बढ़ती मांग इस दृष्टिकोण से बढ़ती मांग की पूर्ति हेतु ऐसी नस्लों का होना आवश्यक है। जो कम लागत पर अधिक उत्पाद कर सके।

शोध का महत्त्व (**Importance of Proposed Research Work**)

पशुधन का कृषक समाज पर सामाजिक–आर्थिक प्रभाव को विषय–वस्तु बनाकर किया जाने वाला अध्ययन शोध क्षेत्र में महत्त्वपूर्ण स्थान रखता है। प्रस्तावित शोध भूगोल विषय के सभी आयामों भौतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं पर्यावरणीय पहलुओं का अध्ययन करता है। इसलिए प्रस्तावित अध्ययन संतुलित आर्थिक, सामाजिक एवं पर्यावरणीय विकास की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण है। इस अध्ययन के माध्यम से पशुपालन, प्रशासन, अर्थशास्त्र, सामाजिक कार्य शोध इत्यादि क्षेत्र में लगे लोगों के लिए उपयोगी होगा।

प्रस्तावित अध्ययन पशुपालन योजनाकर, सामाजिक, कार्यकर्त्ता, प्रशासन, अर्थशास्त्रियों, पशुपालकों, पर्यावरणविदों द्वारा पशुपालन की उपयोगिता तथा कृषक समाज के परिप्रेक्ष्य में इनकी आवश्यकता को समझाने में उपयोगी सिद्ध होगा। अध्ययन कृषक समाज की सामाजिक व आर्थिक परिस्थितियों का विश्लेषणात्मक

विवरण किया जा सकेगा तथा पशुपालन व्यवसाय की आधुनिक आवश्यकताओं को समझा जा सकेगा।

अध्ययन का उद्देश्य

पशुपालन की स्थिति एवं कृषक समाज के सामाजिक–आर्थिक विकास पर प्रभाव का मूल्यांकन करने हेतु सम्पन्न किया गया । इस कार्य के निम्नांकित उद्देश्य निर्धारित किये गये है–

1. अध्ययन क्षेत्र की भौगोलिक, आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति का अध्ययन करना।
2. अध्ययन क्षेत्र में पशुपालन की वर्तमान दशा एवं स्तर का विश्लेषण करना।
3. अध्ययन क्षेत्र में पशुपालन से कृषक समाज पर सामाजिक–आर्थिक प्रभावों का मूल्यांकन करना।
4. अध्ययन क्षेत्र सें पशुपालन विकास के लिए उपलब्ध आवश्यक आधारभूत ढाँचा ज्ञात करना।
6. क्षेत्र में कृषि एवं पशु आधुनिकीकरण का स्तर ज्ञात करना।
7. क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में पशुपालन का योगदान ज्ञात करना।
8. अध्ययन क्षेत्र में पशुपालन को ओर अधिक प्रभावी बनाने के लिए सुझाव प्रस्तुत करना।
9. क्षेत्र में वैज्ञानिक नवाचार से पशुपालन का सतत् विकास का मॉडल प्रस्तुत करना।

परिकल्पनाएँ (Hypothesis)

1- पशुपालन हेतु आधारभूत सुविधाओं के अभाव के कारण इस व्यवसाय की वृद्धि अपेक्षाकृत धीमी रही है।
2. कृषि के यंत्रीकरण एवं आधुनिकीकरण के फलस्वरूप पशुपालन के विकास पर नकारात्मक प्रभाव रहा है।
3. कृषक समाज के आर्थिक स्तर को स्थिरता प्रदान करने में पशुपालन का महत्त्वपूर्ण योगदान रहा है।

राजस्थान में पशु–सम्पदा का विशेष रूप से आर्थिक महत्त्व माना गया है। राज्य के कुल क्षेत्रफल का 61 प्रतिशत मरुस्थलीय प्रदेश है, जहाँ जीविकोपार्जन का मुख्य साधन पशुपालन ही है। इससे राज्य की शुद्ध घरेलू उत्पत्ति का महत्त्वपूर्ण अंश प्राप्त होता है। राजस्थान में देश के पशुधन का 7 प्रतिशत था, जिसमें भेड़ों का 25 प्रतिशत अंश पाया जाता है।

1. राजस्थान में देश के कुल दुग्ध उत्पादन का अंश लगभग 12.73 प्रतिशत होता है।
2. राज्य के पशुओं द्वारा भार–वहन शक्ति 35 प्रतिशत है।
3. भेड़ के माँस में राजस्थान का भारत में अंश 30 प्रतिशत है।
4. ऊन में राजस्थान का भारत में अंश 40: है। राज्य में भेंड़ों की संख्या समस्त भारत की संख्या का लगभग 25 प्रतिशत है।

राजस्थान की अर्थव्यवस्था के बारे में यह कहा जाता है कि यह पूर्णत कृषि पर निर्भर करती है तथा कृषि मानसून का जुआ मानी जाती है। इस स्थिति में पशुपालन का महत्त्व और भी अधिक बढ़ जाता है। राजस्थान में पशुधन का महत्त्व निम्नलिखित तथ्यों से देखा जा सकता है–

राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में योगदान

राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में पशुधन का योगदान लगभग 10% प्रतिशत है।

निर्धनता उन्मूलन

निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रम में भी पशु–पालन की महत्ता स्वीकार की गई है। समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम में गरीब परिवारों को दुधारु पशु देकर उनकी आमदनी बढ़ाने का प्रयास किया गया था। लेकिन इसके लिए चारे व पानी की उचित व्यवस्था करनी होती है तथा लाभान्वित परिवारों को बिक्री की सुविधाएं भी प्रदान करनी होती हैं।

रोजगार–सृजन

पशुपालन में ऊँची आमदनी व रोजगार की संभावनाएँ निहित हैं। पशुओं की उत्पादकता को बढ़ाकर आमदनी में वृद्धि की जा सकती है। राज्य के शुष्क व अर्द्ध–शुष्क भागों में कुछ परिवार काफी संख्या में पशुपालन करते है और इनका यह कार्य वंश–परम्परागत चलता आया है। इन क्षेत्रों में शुद्ध घरेलू उत्पत्ति का ऊँचा अंश पशुपालन से सृजित होता है। इसलिए मरु अर्थव्यवस्था मूलतः पशु–आधारित है।

डेयरी विकास

पशुधन की सहायता से ग्रामीण दुग्ध उत्पादन को शहरी उपभोक्ताओं के साथ जोड़कर शहरी क्षेत्र की दुग्ध आवश्यकता की आपूर्ति तथा ग्रामीण क्षेत्र की आजीविका की व्यवस्था होती है। राजस्थान देश के कुल दुग्ध उत्पादन का 10 प्रतिशत उत्पादन करता है।

परिवहन का साधन

राजस्थान में पशुधन में भार वहन करने की अपार क्षमता है। बैल, भैंसे, ऊँट, गधे, खच्चर आदि कृषि व कई परियोजनाओं में बोझा ढोने व भार खींचने का काम करते हैं। देश की कुल भार वहन क्षमता का 35 प्रतिशत भाग राजस्थान के पशु वहन करते है। देश में रेल व ट्रकों द्वारा कुल 30 करोड़ टन माल की ढुलाई होती है, जबकि बैलगाडियों से आज भी 70 करोड़ टन माल ढोया जाता है।

खाद की प्राप्ति

पशुपालन के द्वारा कृषि के लिए खाद की प्राप्ति भी होती है। इस समय जानवरों के गोबर से निर्मित "वर्मी कम्पोस्ट" खाद्य अत्यधिक प्रचलन में है।

राजस्थान में 20वीं पशुगणना

20वीं पशुगणना के अनुसार राजस्थान में कुल पशुधन 5.68 करोड़ है। जो वर्ष 2012 की पशुगणना में 5. 77 करोड़ था। इस प्रकार 2019 में कुल पशुओं की संख्या में 1.66 प्रतिशत की कमी देखी गई है।

वर्तमान में राजस्थान पशुओं की संख्या की दृष्टि से भारत में दूसरे स्थान पर है? पहला स्थान उत्तर–प्रदेश का है। राजस्थान गोवंश के मामले में 2019 में 13.9 मिलियन जो 2012 में 13.3 मिलियन थे। गोवंश में 4.41 प्रतिशत की वृद्धि हुई है तथा राजस्थान का भारत में 6वां स्थान है। राजस्थान भैंसों के मामले में 2012 में 13.0 मिलियन की तुलना में 2019 में 13.7 मिलियन पशुओं के साथ दूसरे स्थान पर है। भैंसों में 5.53 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। राज्य में भेड़ की संख्या 2012 के 9.1 मिलियन

की तुलना में 2019 में 7.9 मिलियन पशुओं के साथ चौथे स्थान पर है। भेड़ में 12.95 प्रतिशत की कमी हुई है। राजस्थान बकरी संख्या में 2012 के 21.67 मिलियन की तुलना में 2019 में 20.84 मिलियन के साथ पहले स्थान पर बकरियों की संख्या में 3.81 प्रतिशत की कमी हुई है। राज्य ऊँट के मामले में 2012 के 3.26 मिलियन की तुलना में 2019 में 2.13 मिलियन के साथ प्रथम 34.69 प्रतिशत की कमी हुई है। राजस्थान घोड़ों के मामले में 2012 के 0.38 मिलियन की तुलना में 2019 में 0.34 मिलियन पशुओं के साथ तीसरे स्थान पर है। घोड़ों की संख्या में 10.85 प्रतिशत की कमी हुई है।

राजस्थान गधों के मामले में 2012 के 0.81 मिलियन की तुलना में 2019 में 0.2 मिलियन पशुओं के साथ पहले स्थान पर है। गधो में 71.37 प्रतिशत कमी हुई है।

20वीं पशुगणना में राजस्थान का पशुधन

पश	कुल संख्या (मिलियन)	भारत में राजस्थान का स्थान	भारत में प्रथम	राज्य में सर्वाधिक	राज्य में न्यूनतम
ब्करी	20.84	प्रथम	राजस्थान	बाड़मेर	धौलपुर
गाय	13.9	छठा	प.बंगाल	उदयपुर	धौलपुर
भैंस	13.7	दूसरा	उत्तर प्रदेश	जयपुर	जैसलमेर
भेड़	7.9	चौथा	तेलंगाना	बाड़मेर	बांसवाड़ा
ऊँट	2.13	प्रथम	राजस्थान	जैसलमेर	प्रतापगढ़
सूअर	–	–	असम	भरतपुर	डूँगरपुर
गधे	0.23	पहला	राजस्थान	बाड़मेर	टोंक
घोड़े	0.34	तीसरा	उत्तरप्रदेश	बीकानेर	डूंगरपुर

स्रोत : पशुपालन, डेयरी मंत्रालय रिपोट

इस प्रकार संख्या की दृष्टि से पशुओं में गाय–बैल तथा भेड़–बकरी प्रमुख हैं। राजस्थान में उपलब्ध विभिन्न जानवरों, जैसे– गाय, बकरी, भेंड आदि का वर्णन निम्नलिखित है–

गाय

राजस्थान में गाय पशुपालन के क्षेत्र में महत्त्वपूर्ण स्थान रखती है। कुल पशु–सम्पदा में गौवंश का 13.9 मिलियन है। इसकी निम्नलिखित नस्लें राजस्थान में पाई जाती हैं–

नागौरी

1. कांकरेज
2. थारपारकर
3. राठी

भेंड़

देश की कुल भेंडों की लगभग 7.9 मिलियन राजस्थान में पाई जाती हैं। राज्य के लगभग 2 लाख परिवार पशुपालन कार्यों में संलग्न हैं। यहाँ पाई जाने वाली भेड़ों की प्रमुख नस्लें इस प्रकार हैं–

1. जैसलमेरी भेड़
2. नाली भेड़
3. मालपुरी भेड़
4. मगरा भेड़
5. पूगल भेड़
6. मारवाड़ी भेड़
7. शेखावाटी भेड़ या चोकला
8. सोनाडी भेड़

राजस्थान में पशुसंख्या (2012–2019)

मिलियन

पशु	2012	2019	वृद्धि
गोवंश	13.3	13.9	+4.41%
भैंसवंश	13.0	13.7	+5.53%
भेड़वंश	9.1	7.9	–12.95%
बकरी	21.67	20.84	–3.81%
ऊँट	3.26	2.13	–34.69%

स्रोत : पशुपालन डेयरी मंत्रालय रिपोर्ट 2019

डॉ. बुद्धि प्रकाश गौत्तम 2005 हाड़ौती क्षेत्र में डेयरी विकास का स्थानिक सामयिक विश्लेषण कर राजस्थान के मध्य पूर्वी जिलों में बढ़ते पशुपालन आवश्यकता को प्रत्यक्ष किया है।

पशुधन विकास की समस्या

मानसून की अनिश्चिता

राजस्थान में प्रायः सूखे की समस्या रहती है। इसी वजह से पशुओं को पर्याप्त मात्रा में चारा उपलब्ध नहीं हो पाता। योजना एवं समन्वय का अभाव– सरकार अभी तक इस क्षेत्र के विकास के लिए एक सम्पूर्ण योजना का खाका तैयार नहीं कर पायी है, तथा समन्वय का अभाव देखा गया है। पशु स्वास्थ्य योजना – अक्सर देखा जाता है कि किसी एक बीमारी के कारण सभी पशु उसकी चपेट में आ जाते हैं। इस स्थिति को समाप्त करने के लिए योजना एवं सुविधाओं का अभाव देखा गया है। पशु आधारित उद्योगों की कमी – राजस्थान में ऊन, दूध तथा चमड़ा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, परन्तु इन पर आधारित उद्योगों की राजस्थान में कमी होने से दूध, चमड़ा दूसरे राज्यों में निर्यात कर देने से राज्य को पर्याप्त लाभ नहीं मिल पाता है।

विकास हेतु समाधान

राजस्थान में पशुधन का बेहरत प्रयोग हो सके और इससे अधिक से अधिक लाभ लिया जा सके, इसके लिए कई कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं। जिनमें से कुछ निम्नलिखित हैं–

भेड़ प्रजनन कार्य

राज्य में ऊन व मांस के उत्पादन में गुणात्मक व मात्रात्मक सुधार करने के लिए भेड़ प्रजनन कार्य में सुधार

के व्यापक प्रयास किए गए हैं। क्रॉस–प्रजनन कार्यक्रम नाली, चोकला, सोनाडी व मालपुरी नस्लों पर लागू किया गया है। इसमें कृत्रिम गर्भाधान के जरिए भेड़ों की नस्ल सुधारी जाती है। इसके अलावा चयनित प्रजनन कार्यक्रम चलाया जा रहा है।

विपणन व्यवस्था

पशुपालकों को उनके उत्पादन का उचित मूल्य प्राप्त हो, इसके लिए एक तरफ पशुओं के क्रय–विक्रय हेतु पशु मेला लगाये जाते हैं। दूसरी तरफ दूध को बिना मध्यस्थों के सीधा उपभोक्ता तक पहुँचाने के लिए दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों की स्थापना की गयी है। राज्य में पशु मेलों का आयोजन ग्राम पंचायत, नगरपालिका एवं पंचायत समितियों के माध्यम से किये जाता है। राज्य में वर्तमान में 50 पशु मेले लगते हैं, जिनमें 10 मेले राज्य स्तरीय प्रसिद्ध पशु मेले, पशुपालन विभाग द्वारा आयोजित किये जाते है।

पशु चिकित्सा

नए पशु चिकित्सा उपकेन्द्र खोले जाने की स्वीकृति जारी की गई है। प्शुपालकों को बेहतर सुविधा उपलब्ध करवाये जाने के लिये आवश्यकतानुसार पषुचिकित्सा संस्थाओं को क्रमोन्नत किया जावेगा तथा निजी क्षेत्र के माध्यम से मोबाइल सेवा प्रारम्भ की जावेगी। प्रदेश में गाय भैस में नस्ल सुधार कार्यक्रम को बढ़ावा दिये जाने के लिए कृत्रिम गर्भाधान सुविधाओं को प्रभावी ढंग से लागू किया जा रहा है।

पशुपालन व अनुसंधान

राज्य में द्वितीय पंचवर्षीय योजना में दो पशु चिकित्सा महाविद्यालय बीकानेर तथा जयपुर में स्थापित किये गये हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने बीकानेर एवं सूरतगढ़ में भेड़ अनुसंधान केन्द्र स्थापित किये हैं। जोधपुर में ऊन एवं भेड़ प्रशिक्षण स्कूल स्थापित किया गया है। विश्व बैंक की सहायता से जामडोली में पशु चिकित्सकों एवं अधिकारियों को विशेष तकनीकी प्रशिक्षण हेतु राजस्थान पशु–धन प्रबंध संस्थान का भवन निर्माण कार्य करवाया है।

निष्कर्ष

प्रदेश में 5.66 करोड पशुधन है जो कि भारतवर्ष का लगभग 11 प्रतिशत हिस्सा है। प्रदेश का देशी गौवंश, बकरीवंश, भेडवंश व मारवाडी घोड़े एवं ऊंट इत्यादि सुविख्यात हैं। राज्य मे समय–समय पर अकाल, अभाव की स्थिति उत्पन्न होती रहती है। ऐसी स्थिति में ग्रामीण क्षेत्रों में पशुपालकों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन पशुपालन ही रहता है। पशुपालन क्षेत्र ग्रामीण जीवन की आर्थिक, सामाजिक एवं पोषण कीं आवश्यकताओं को पूरा करने का मुख्य स्त्रोत है।पषुपालन से बेरोजगारों को स्वरोजगार का बेहतर विकल्प मिला है।

प्रदेश की देशी गौवंशीय नस्लों के संरक्षण, संवर्धन, स्वास्थ्य एवं विकास को सर्वाधिक महत्व देने के लिए अधिकांश ग्राम पंचायतों में विभागीय पशु चिकित्सा संस्थाओं के अतिरिक्त निजी क्षेत्र में भी एकीकृत पशुधन विकास केन्द्र संचालित किये जा रहे है। वर्ष 2019–20 में 400 एवं वर्ष 2020–21 में 200 रहा है। अवांछित नर बछड़ों की संख्या में कमी लाने एवं उत्पादकता में वृद्वि के लिए अनुदानित दर पर कृत्रिम गर्भाधान हेतु सॉर्टेड सीमन के उपयोग की योजना प्रारम्भ की जा रही है। प्रदेश की पशुचिकित्सा सेवाओं को सुदृढ़ करने एवं उसे और अधिक आधुनिक बनाने हेतु प्रत्येक पशुचिकित्सालय में राजस्थान पशुचिकित्सा रिलीफ सोसायटी का गठन किया जा रहा है। प्रदेश के प्रगतिशील पशुपालकों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से राज्य स्तरीय पशुपालक सम्मान समारोह आयोजित किया जायेगा। ऊँटों की लगातार घटती संख्या को रोकने तथा ऊँट प्रजनन को बढ़ावा दिये जाने के उद्देश्य से ऊटों के संरक्षण व संवर्धन के लिए विशेष नीति बनाई जायेगी। पशुओं के बेहत्तर स्वास्थ्य के लिए पशुओं का व्यापक टीकाकरण कार्यक्रम चलाया जा रहा है। जिसे आगामी वर्षो में और व्यापक बनाया जायेगा। पशुधन निःशुल्क आरोग्य योजना अन्तर्गत निरन्तर पशुओं के उपचार हेतु विभिन्न प्रकार की दवाएँ निःशुल्क उपलब्ध करायी जा रही है, जिससे पशुओं के स्वास्थ्य एवं उत्पादन में सुधार हो रहा है। पशु स्वास्थ्य की इन योजनाओं के परिणाम सराहनीय है।

सन्दर्भ ग्रंथ सूची

1. *Behnke, R.H. and Scoones, I. 1993. Rethinking range ecology: implications for rangeland management in Africa. In: Behnke, R.H. Scoones, I. and Kerven, C. (eds.) Range Ecology at*
2. *Disequilibrium: New Models of Natural Variability and Pastoral Adaptation in African Savannas. Overseas Development Institute, London.*
3. *Cooksley D.G., Prinsen J.H., Paton C.J. and Pini J.A. 1991. Performance of a beef cattle production system on native pasture using Leucaena leucocephala as a supplement. Livestock Production Science, 28, 65-72.*
4. *De Boer, J. 1992. Technological and socioeconomic changes: including urbanization, as they impact upon animal production in Asia. Animal Production and Rural Development:*
5. *Proceedings of the Sixth AAAP Animal Science Congress. Vol I. Bangkok. p 57-72.*
6. *El-Serafy A.M., Aboul-Naga A.M. and Galal E.S.E. 1992. Cereal Grain Input in the Small Ruminant Production System in the Coastal Zone of Western Desert of Egypt. Proceedings of the Joint ANPA-EAAP-ICAMAS Symposium, Rabat, October 1990, No. 49.*
7. *FAO/IFAD. 1982. Report of the Sudan Stock Route Development Project: Preparation Mission. Investment Centre. Report No. 10/82 DDC/SUD 18.*
8. *FAO. 1982. Report on the agro-ecological zones project - Methodology and results for Africa. 185pp.*
9. *FAO. 1992. Review of CGIAR priorities and strategies - Part I: TAC. Rome. FAO. 250 p.*
10. *FAO. 1994. Information System for Agricultural Statistics (Agrostat) Database.*
11. *Fernandez-Baca S, De Lucia Silva, G.R., Jara L.C. 1986. Milk and beef production from tropical pastures: an experience in the humid tropics. World Animal Review (FAO) No. 58 p. 2-12. Rome.*

12. *Garcia Betancourt E. & Garcia Betancourt O. 1993. Aspectos productivos de caprinos mestizosde alpino frances y nubian con criollo bajo condiciones de cria extensiva en Venezuela. Etudes*
13. *et Syntheses de l'IEMVT. No. 42. Pathologie caprine et productions, 2e Colloque international de NIORT, June 1989.*
14. *Hecht, S. 1993. The logics of livestock and deforestation in Amazonia: directly unproductive, but profitable investments (DUPs) and development. In: Proceedings VII World Conference on*
15. *Animal Production, Edmonton, Alberta, Canada. June 28 - July 2, 1993. Volume 1. p 41-62.*
16. *Humphrey, J. 1980. The classification of world livestock systems. A study prepared for the Animal Production and Health Division. FAO. AGA/MISC/80/3.*
17. *International Monetary Fund. 1992. International Financial Statistics Yearbook.*
18. *Jahnke, H.E. 1982. Livestock production systems and livestock development in tropical Africa.*